उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 9-10 1-31 मई 2021 संयुक्तांक ₹ 20/-

पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर
- कतर के वित्त मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त
- जर्मनी में जिहादी संगठन पर प्रतिबंध
- पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश

राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर
विधानसभाओं के चुनाव उर्दू समाचारपत्रों की नजर में
उत्तर प्रदेश में अवैध भवनों को गिराए जाने पर मच बवाल
लक्षद्वीप में प्रशासन के विकास कार्यक्रम का विरोध
जमीयत उलेमा के अध्यक्ष का निधन

विश्व

जर्मनी में जिहादी संगठन पर प्रतिबंध
अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के लिए अमेरिकी विमान
काबुल में हुए धमाके में 50 छात्राओं की मौत
चीन अफ्रीका में फैला रहा है अपने पांव
अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति की विद्रोहियों द्वारा हत्या

पश्चिम एशिया

पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक
मिस्र फ्रांस से राफेल विमान खरीदेगा
सऊदी अरब में क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर देश से निष्कासन
ईरान मोरक्को के लिए खतरा
कतर के वित्तमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त

अन्य

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन
सऊदी अरब से 1100 पाकिस्तानी कैदी वापस
अमेरिकी नौसेना ने अस्त्र-शस्त्र जब्त किए
यरुशलम में बाबा फरीद की सराय
इमरान खान का सऊदी दौरा

सारांश

यूरोप के लगभग सभी देश इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से काफी परेशान हैं। जर्मनी ने हाल ही में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अंसार इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि मस्जिदों और मदरसों में अतिवादी इस्लाम का प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए।

पश्चिम एशिया में इजरायल और फिलिस्तीनी अरबों के बीच हाल ही में जो खूनी संघर्ष हुआ है वह एक गंभीर संकेत है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील पर दोनों पक्षों ने युद्धविराम को स्वीकार कर लिया है। मगर यह कहना कठिन है कि यह शांति कब तक बरकरार रहेगी। दोनों पक्ष लम्बे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रयासों से अरब देशों के साथ इजरायल को अपने संबंध सुधारने का मौका मिला है। गत एक वर्ष में अरब जगत के छह मुस्लिम देशों ने अमेरिकी दबाव पर इजरायल को न सिर्फ मान्यता दी है बल्कि अपने देश में इजरायलियों के लिए दरवाजे भी खोल दिए हैं। यह आम चर्चा थी कि सऊदी अरब भी इजरायल को मान्यता दे देगा। मगर अभी तक सऊदी अरब ने इजरायल को मान्यता देने की घोषणा नहीं की है। यही कारण है कि हाल के इजरायल और हमास के संघर्ष में तुर्की को छोड़कर लगभग अन्य सभी अरब देश तटस्थ रहे। भारत के भी हाल ही में इजरायल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंध सुदृढ़ हुए हैं। जबकि प्रारम्भ से ही भारत फिलिस्तीनी जनता का समर्थन करता आया है। आजादी के लगभग 50 वर्ष गुजर जाने के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने इजरायल को मान्यता दी थी। मोदी के सत्ता में आने के बाद इजरायल का भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। इसलिए भारत इस दुविधा में था कि वह इस मामले में क्या नीति अपनाए। भारत सरकार का सारा जोर इस बात पर था कि इस क्षेत्र में युद्ध खत्म हो और शांति की स्थापना हो। इजरायल के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव आया था भारत ने उसका समर्थन नहीं किया और तटस्थ बना रहा।

उत्तर प्रदेश में चुनाव की चर्चा शुरू होते ही विपक्षी दलों ने मुस्लिम मतदाताओं को योगी सरकार के खिलाफ भड़काने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बाराबंकी और मुजफ्फर नगर में सरकारी जमीन पर बने दो भवन प्रशासन ने गिरा दिए थे। प्रशासन के अनुसार ये दोनों भवन अवैध रूप से बनाए गए थे और उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देश पर गिराया गया है। मगर सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बाराबंकी के राम सनेही घाट पर जिस गरीब नवाज मस्जिद को गिराया गया है वह सुन्नी वक्फ बोर्ड की सूची में शामिल थी। जबकि प्रशासन इस बात से इंकार करता है। पुलिस ने मस्जिद की प्रबंध समिति के साथ-साथ वक्फ बोर्ड के तत्कालीन इंस्पेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस केस के आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। जहां तक मुजफ्फर नगर का संबंध है वहां पर जब प्रशासन इस अवैध ढांचे को ध्वस्त करने के लिए पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। मुस्लिम संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन अवैध भवनों को जिन अधिकारियों ने गिराया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर

इंकलाब (10 मई) के अनुसार हसन खालिद नामक पत्रकार ने अपनी विशेष रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में मुस्लिम विश्वविद्यालय के 44 प्रोफेसर दम तोड़ चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रोफेसर भी शामिल हैं जो कि रिटायर्ड होने के बावजूद मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में रह रहे थे। इनमें विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। बताया जाता है कि 333 अशैक्षणिक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 150 वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक साथ इतने प्रोफेसरों की मौत हुई है। इनके अतिरिक्त 100 से अधिक प्रोफेसर जे.एन. मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं। जो लोग मरे हैं वे अपने-अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ थे। मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने इस संदर्भ में एक पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी भेजा है। जबकि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलोजी विभाग में रखे हुए कोरोना संक्रमितों के जो वायरल जीनोम थे उन्हें दिल्ली स्थित महामारी जांच संस्थान में भेजा गया है। प्रो. तारिक मंसूर ने आईसीएमआर के महानिदेशक प्रो. बलराम भार्गव से अनुरोध किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सिविल लाइन क्षेत्र में फैले हुए वायरल जीनोम के बारे में विशेष जांच करवाई जाए क्योंकि इस विशेष वायरल के कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं।

इंकलाब (11 मई) में ही प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 के लगभग बताई जाती है। इनमें विश्वविद्यालय से संबंधित 50 से अधिक अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।

इंकलाब (13 मई) के अनुसार सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिस तरह से भारी संख्या में प्रोफेसरों की मृत्यु हो रही है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि भारत सरकार विशेषज्ञों की एक विशेष टीम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जांच के लिए तुरंत भेजे।

एक अन्य समाचार के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विट करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोविड के कारण हो रही मौतों पर चिंता प्रकट की है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तुरंत जांच करवाने की मांग की है।

रोजनामा सहारा (15 मई) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति को भेजे गए पत्र में कोविड के कारण हो रही मौतों पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि भारत सरकार इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को वहां भेज रही है।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के साथ अलीगढ़ पहुंचे। 33 वर्ष के बाद यह पहला अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री मुस्लिम विश्वविद्यालय में आया हो। इससे पहले 1988 में नारायण दत्त तिवारी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय का दौरा किया था। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और इस बात का आश्वासन दिया कि इस मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन और दवाइयों को उपलब्ध करवाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. तारिक मंसूर, रजिस्टार अब्दुल हमीद, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. शाहिद अली सिद्दीकी और डीन ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर राकेश भार्गव आदि से भी एक घंटे तक विचार विमर्श किया और उन्हें राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

विधानसभाओं के चुनाव उर्दू समाचारपत्रों की नजर में

उर्दू के अधिकांश समाचारपत्रों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पुनः सत्ता में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

इंकलाब (3 मई) ने इन चुनाव परिणामों को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है। इस समाचार के अनेक उपशीर्षक भी दिए गए हैं। शीर्षक हैं, 'ममता ने फिर किया बंगाल फतह', 'भाजपा को शिकस्त', 'पीएम से लेकर पूरे मंत्रिमंडल की ताकत झोंकने के बावजूद 81 सीटों पर सिमट गई बीजेपी', 'टीएमसी को मिली 209 सीटें', 'कांग्रेस और वाम मोर्चा का नहीं खुला खाता', 'असम में कांग्रेस-एआईयूडीएफ का नहीं चला जादू', 'तमिलनाडु में कांग्रेस की इज्जत बची', 'केरल में वाम मोर्चा दूसरी बार जीता', 'पांडिचेरी में कांग्रेस की हार'।

इन चुनावों पर टिप्पणी करते हुए **इंकलाब** (3 मई) ने अपने संपादकीय में भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी का मतलब है "बहुत जूते पड़े।" ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जो भारी कामयाबी मिली है इससे बीजेपी को बड़ी

जिल्लत का सामना करना पड़ा है। हालांकि चुनाव तो चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में था मगर इन चारों के बारे में न तो भाजपा को कोई चिंता थी और न ही गोदी मीडिया को इनमें कोई रुचि थी। इसका कारण यह था कि वहां के चुनाव परिणाम पहले से ही लगभग तय थे। वहां के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का कोई तरीका भाजपा को मालूम नहीं था। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी।

वैसे भी भाजपा ने गत सवा वर्ष से बंगाल में अपना चुनावी अभियान छेड़ रखा था। बंगाल के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की पूरी ताकत से कोशिश कर रखी थी और गोदी मीडिया उसका साथ दे रहा था। बंगाल से दूर बैठे लोगों को लगने लगा था कि इस बार तो ममता बनर्जी का तख्ता पलटने में मोदी जी और उनके भक्त सफल हो जाएंगे। अमित शाह ने तो बार-बार यह दावा किया कि इस बार 200 से ज्यादा सीटें वे ले आएंगे। बंगाल का चुनाव भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ऐसे सवार था कि उसने सारे देश से किराए के कार्यकर्ताओं को बुला रखा था जो वहां बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे थे और बंगाली बोलने वाले काली और दुर्गा के श्रद्धालुओं में साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रहे थे। मोदी जी ने तो चुनाव से दो महीने पूर्व ही किसी न किसी बहाने से हर रोज टेलिवीजन पर भाषणों का सिलसिला शुरू कर रखा था।

भाजपा और उसकी गोदी मीडिया ने यह समझ लिया था कि प्रचार से जनता को गुमराह किया जा सकता है। बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने खजानों के मुंह खोल रखे थे और तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को खरीदना शुरू कर रखा था। हद तो यह है कि उसने अपने सांसदों और मंत्रियों तक को चुनावी मैदान में उतार दिया था। मगर नतीजा आपके सामने है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि

यह पूरा चुनाव मोदी और अमित शाह के नाम पर लड़ा गया। अब बंगाल में बुरी तरह से हारने की जिम्मेवारी भी इन दोनों को ही ले लेनी चाहिए।

रोजनामा सहारा (3 मई) ने इस समाचार का शीर्षक दिया है, 'पश्चिम बंगाल में ममता की हैट्रिक', 'असम में बीजेपी', 'केरल में वाम दल की वापसी'। समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि पहले राज्यों के चुनाव उस राज्य तक ही सीमित होते थे। मगर अब मीडिया में हुई प्रगति के कारण ये देश भर के चुनाव बन गए हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की जीत को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। इसलिए कोरोना की महामारी की तबाही को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी। मगर इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि इतने जबर्दस्त चुनाव प्रचार के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से यह साफ संदेश मिल गया है कि किसी लहर के सहारे या खोखली नारेबाजी से चुनाव नहीं जीते जा सकते।

एक चुनाव विशलेषक अब्बास धारीवाल ने इन चुनावों में बीजेपी की हार के पीछे किसान आंदोलन का संकेत दिया है और कहा है कि जिस तरह से भाजपा ने जीत हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को आठ चरणों में खींचा था वह दांव भाजपा को उल्टा पड़ गया। कांग्रेस सिर्फ असम और केरल में एक विपक्षी दल का दर्जा ही प्राप्त कर सकी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार से यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब देश में भाजपा और मोदी का जादू समाप्त हो गया है।

हमारा समाज (4 मई) ने इन चुनावों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा के विभाजक प्रचाार का शिकार नहीं बनी और उसने सेक्युलर विचारधारा का साथ दिया है।

दैनिक सियासत (4 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता मतदाताओं को गुमराह करने में विफल रहे हैं।

रोजनामा सहारा (4 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या में कमी आई है। पुरानी विधानसभा में 59 मुस्लिम विधायक थे। अब उनकी संख्या घटकर 42 ही रह गई है। बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या 27 प्रतिशत है। 60 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। जबकि 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 40 से 50 प्रतिशत के बीच है। मगर इस बार तृणमूल कांग्रेस ने 42 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। हालांकि पिछली विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या 30 थी। जबकि इस बार बढ़कर 41 हो गई है। जबकि 1 विधायक राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी का जीता है। पिछली विधानसभा में वामपंथी मोर्चा के 9 मुस्लिम विधायक थे और कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या 18 थी। मगर इस बार इन दोनों पार्टियों का कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं रहा।

इत्तेमाद (4 मई) ने इसे हिंदूवादी विचारधारा की हार करार दिया है और कहा है

कि इन चुनावों में ममता बनर्जी को सत्ता में लाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है।

इंकलाब ने 4 मई के अंक में एक विशेष संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट विभाजित नहीं हुए। इसीलिए भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए न तो विकास का नाम लिया न ही किसी सैनिक कार्रवाई को ही चुनाव का मुद्दा बनाया। वहां पर उसने पूरी तरह से साम्प्रदायिकता को चुनाव का मुद्दा बनाया और जय श्रीराम का सहारा लिया। गोदी मीडिया की ओर से ममता को सिर्फ मुसलमानों की नेता ही बताया जा रहा था। मुसलमानों के वोटों को विभाजित करने की भी कोशिश की गई।

हैदराबाद से चलकर ओवैसी साहब बंगाल के मैदान में उतर गए और फुरफुरा शरीफ के सज्जादानशीन से मिले और मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। मगर फुरफुरा शरीफ के सज्जादानशीन इनसे भी ज्यादा स्मार्ट निकले। उन्होंने पहले तो बहुत गर्मजोशी से ओवैसी का स्वागत किया और बाद में अपनी अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस और वामदल से मिलकर चुनाव लड़ने का खेल खेल ड़ाला। इस बेचारे ने यह सोचा था कि वे मुसलमानों को जो पाठ रटाएंगे वे फटाफट पढ़ देंगे। मगर बंगाल के मुसलमानों ने यह बता दिया कि वे इस देश की राजनीति को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोट विभाजित करने वाली पार्टियों को ईवीएम से बाहर निकालकर फेंक दिया। बल्कि वामपंथी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों को भी यह समझकर अपने वोट नहीं दिए कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए उनको वोट देना अपने वोट बर्बाद करना होगा। सेक्युलर हिंदुओं ने भी मुसलमानों के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता सौंप दी है। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और इनमें से 41 सफल हुए। सिर्फ एक उम्मीदवार करीम रजा को मुसलमानों की स्थानीय पार्टी राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी के उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी ने हराया। बंगाल में सेक्युलर हिंदुओं और मुसलमानों की जबर्दस्त समझदारी के कारण वोट विभाजित नहीं हुए। वरना बीजेपी को काफी लाभ हो जाता।

समाचारपत्र का कहना है कि फुरफुरा शरीफ के सज्जादानशीं अब्बास सिद्दीकी की समझ में अब यह बात आ गई होगी कि दरगाहों की आड़ लेकर उसने जो राजनीतिक खेल शुरू किया था वह मुसलमानों को पसंद नहीं आया। हद तो यह है कि ओवैसी साहब के हीरे मोती भी बंगाल में अपनी चमक-दमक नहीं दिखा पाए।

असम में मौलाना बदरूद्दीन अजमल ने कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा का बहुत सख्त मुकाबला किया। मगर वे वहां साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन के 50 उम्मीदवार चुनाव जीते जिनमें से 30 मुसलमान हैं।

उत्तर प्रदेश में अवैध भवनों को गिराए जाने से मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और मुजफ्फर नगर में दो अवैध ढांचों को राज्य सरकार द्वारा ध्वस्त किए जाने के कारण जबर्दस्त बवाल मच गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह दावा किया है कि जिन दोनों भवनों को अवैध करार देकर प्रशासन ने गिराया है वे मस्जिदें थीं। उसने इसके खिलाफ जनांदोलन चलाने और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की घोषणा की है।

इंकलाब (19 मई) में प्रकाशित एक समाचार में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज 100 वर्ष पुरानी मस्जिद गरीब नवाज उर्फ तहसील वाली मस्जिद को राम सनेही घाट के एसडीएम देवांश पटेल ने गैरकानूनी निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया है। उनकी इस कार्रवाई की सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निंदा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फारूकी का कहना है कि इस मस्जिद को प्रशासन ने जानबूझकर गिराया है और वे इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन सारे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उसने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को जो निर्देश दिए थे उसका प्रशासन ने खुला उल्लंघन किया है। प्रशासन का कहना है कि इस मस्जिद का विवाद काफी समय से चल रहा है। क्योंकि राज्य सरकार का यह निर्देश है कि सरकारी जमीन और सड़कों पर बनाई गई सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाए। उसने कहा कि इस संदर्भ में मस्जिद के मुतवल्ली मुस्ताक अहमद को एक नोटिस भी जारी किया था। मगर उन्होंने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज ही पेश किया जिससे यह सिद्ध हो कि यह मस्जिद सरकारी भूमि पर नहीं बनी है। इसके बाद इस मस्जिद की प्रबंध समिति ने इलाहाबाद उच्च

न्यायालय में भी यह मामला उठाया मगर न्यायालय में भी वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। न्यायालय ने मस्जिद की प्रबंध समिति को 15 दिन का समय दिया था ताकि वे इस इमारत पर अपने मालिकाना और सरकारी भूमि पर यह निर्माण कैसे और किसके आदेश पर हुआ है इसका सबूत पेश करें। इसके जवाब में प्रबंध समिति कोई सबूत पेश करने में विफल रही। इस पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम ने इस गैरकानूनी भवन को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। इस पर भारी पुलिस पहरे में जब प्रशासन ने इस मस्जिद को ध्वस्त किया तो उसका लोगों ने विरोध किया जिस पर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

इंकलाब (29 मई) के अनुसार इस अवैध ढांचे की प्रबंध समिति और उस समय के वक्फ इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रशासन ने एक मुकदमा दर्ज किया और कहा कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से सरकारी भूमि पर किया गया जिसे तत्कालीन वक्फ इंस्पेक्टर ने इसकी प्रबंध समिति से गठजोड़ करके इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467 आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके खिलाफ आरोपियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह मांग की थी कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। इस याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि वे पुलिस द्वारा जांच में उसे पूरा सहयोग दें।

इंकलाब (25 मई) के अनुसार अली हजरत के प्रवक्ता ने कहा है कि दरगाह अली हजरत के प्रमुख मोहम्मद सुजान रजा खान ने मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की निंदा की है और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि इसका नवनिर्माण तुरंत करवाया जाए और जिन अधिकारियों ने यह शरारत की है उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बरेलवी सम्प्रदाय इसके खिलाफ राज्य भर में जनांदोलन चलाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 मई) में प्रकाशित समाचार के अनुसार मुजफ्फर नगर की मस्जिद अल जमील को भी प्रशासन ने गिरा दिया है। यह मस्जिद मुजफ्फर नगर के कस्बा खतौली में स्थित थी। वहां पर पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मस्जिद गैरकानूनी नहीं थी और उनके पास इससे संबंधित सभी प्रमाण मौजूद हैं। मगर प्रशासन ने इनको देखना जरूरी नहीं समझा।

लक्षद्वीप में प्रशासन के विकास कार्यक्रम का विरोध

इन दिनों केरल के तट के समीप स्थित लक्षद्वीप विवाद का केन्द्र बना हुआ है। स्थानीय मुस्लिम नेताओं द्वारा इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपाई प्रशासन भगवाकरण को लादने का प्रयास कर रहा है। मुस्लिम नेता इस मुद्दे को उछालने में जुटे हुए हैं।

लक्षद्वीप 36 टापुओं वाला मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है, जिसकी जनसंख्या 65000 बताई जाती है। इसकी 99 प्रतिशत जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा करने का प्रयास किया था मगर त्रावनकोर-कोचीन के तत्कालीन मुख्यमंत्री पी. गोविंद मेनन की सतर्कता के कारण यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बच गया। यह द्वीप समूह उस समय भी चर्चा में आया था जब 1987 में राजीव गांधी अपने परिवार और मित्रों के साथ नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विराट पर पिकनिक मनाने लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप से अब तक मुस्लिम सांसद ही निर्वाचित होता रहा है। जनजाति बहुल द्वीप समूह का इस्लामीकरण सातवीं शताब्दी में हुआ था। एक इस्लामिक प्रचारक मियां अब्दुल्लाह ने जेद्दा से आकर यहां पर कदम रखा था। हाल ही में इस द्वीप समूह का प्रशासक प्रफुल्ल खोडाभाई पटेल को बनाया गया है जो कभी नरेन्द्र मोदी मंत्रीमंडल में गुजरात के गृहमंत्री हुआ करते थे। पटेल ने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक विकास योजनाओं को शुरू किया है, जिसके तहत लक्षद्वीप की संकरी जर्जर सड़कों का

नवीनीकरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। पटेल का लक्ष्य इस द्वीप समूह को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का है। इसलिए उन्होंने एक कानून लागू किया है जिसके अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था है। उनका यह प्रयास मुस्लिम लीग के स्थानीय नेताओं को पसंद नहीं आया और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आरोप यह लगाया गया है कि हालांकि इस द्वीप समूह की बड़ी आबादी मुस्लिम है इसके बावजूद क्षेत्र में गोमांस की बिक्री बंद कर दी गई है और शराब की दुकानें खुलवा दी गई हैं और दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटेल का दावा है कि वे इस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। उनका इरादा होटलों का निर्माण करवाने और मछलियों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज

स्थापित करने का है। हाल ही में इस क्षेत्र से काफी मात्रा में मादक पदार्थ और अवैध अस्त्र-शस्त्र भी बरामद हुए हैं। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मालदीव में सक्रिय चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपने पैर पसारना चाहते हैं।

दैनिक इंकलाब ने 28 मई के अंक में लक्षद्वीप के समाचार को मुख्य समाचार बनाया है, जिसका शीर्षक दिया है, 'लक्षद्वीप में साम्प्रदायिकता का खेल'। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ वहां के सभी नेता परेशान हैं और भाजपा के नेताओं ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। समाचारपत्र के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा के 8 पदाधिकारियों ने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है। युवा मोर्चा के महामंत्री पी.पी. मोहम्मद हासिम ने आरोप लगाया है कि हम इन द्वीपों के विकास के लिए भाजपा में शामिल हुए थे। मगर प्रशासक जानबूझकर लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए हमलोगों ने त्यागपत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री से वर्तमान सांसद मोहम्मद फैजल ने भी एक पत्र लिखकर विरोध प्रकट किया है और कहा है कि प्रशासक लोगों के पारम्परिक जीवन पद्धति में अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रशासक को वापस बुलाया जाए। राज्य सभा के सदस्य ई. करीम ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर पटेल को वापस बुलाने का अनुरोध किया है और कहा है कि पटेल ने शराब की दुकानें खोलने और गोमांस बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके कराण भारी जनाक्रोश है।

समाचारपत्र के अनुसार वहां की जनता मोदी सरकार और प्रशासक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि लक्षद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां की अनूठी संस्कृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। वहां के प्रशासन ने जो नीतियां अपनाई है वह जनता विरोधी है। इसलिए इन नीतियों को वापस लिया जाए।

इंकलाब (30 मई) के अनुसार एसआईओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने यह आरोप लगाया है कि प्रशासक जानबूझकर लक्षद्वीप का भगवाकरण कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भूमि अधिग्रहण के बारे में जो कानून लागू किया है वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हित में है और उनके हितों के लिए लोगों को संपत्ति से वंचित किया जा रहा है।

रोजनामा सहारा (29 मई) ने इस संबंध में एक संपादकीय प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि प्रशासक जानबूझकर इस द्वीप समूह की परम्परागत संस्कृति और विरासत को समाप्त कर रहे हैं और वे परम्परागत जीवन पद्धति को समाप्त करना चाहते हैं। अभी तक इस क्षेत्र में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध था मगर अब वहां पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह सीधे-साधे इस्लामिक जीवन पद्धति में हस्तक्षेप है। इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। संपादक ने मांग की है कि लक्षद्वीप में जो भी नीति सरकार लागू करना चाहती है उसे स्थानीय लोगों की मर्जी से ही लागू किया जाना चाहिए

और इस संबंध में किसी तरह की जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए।

इंकलाब (31 मई) के अनुसार मुस्लिम चिंतक प्रो. अख्तरूल वासे ने कहा है कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रधानमंत्री मोदी की 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति में पलीता लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बार इस क्षेत्र का प्रशासक एक राजनीतिज्ञ को नियुक्त किया गया है जो मुसलमानों पर भगवाकरण की नीति को जबरन लागू कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रशासक ने जो भी निर्णय किए हैं उन्हें तुरंत रद्द किया जाए।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष का निधन

इंकलाब (22 मई) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख व जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उनकी गणना विश्वविख्यात इस्लामिक चिंतकों और विद्वानों में की जाती थी। उनका जन्म मुजफ्फर नगर के मंसूरपुर में 1944 में हुआ था। उन्होंने दारूल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की। 1982 में वे दारूल उलूम देवबंद में अध्यापक नियुक्त हुए जहां उन्होंने 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। 2010 में देवबंद के प्रबंधक मौलाना मरघुबुर रहमान बिजनोरी के निधन के बाद उन्हें इमारत-ए-शरिया के अनुसार अमीर-उल-हिंद घोषित किया गया था। 1979 में मौलाना असद मदनी ने 'मिल्लत बचाओ' आंदोलन शुरू किया था जिसके तहत मौलाना मंसूरपुरी जेल भी गए थे।

रोजनामा सहारा (23 मई) के अनुसार मौलाना को देवबंद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मौलाना के निधन पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संवेदना प्रकट की है। सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने अपने संदेश में कहा है कि मौलाना ने देश और मिल्लत की जो सेवाएं की हैं उसे कभी भूला नहीं किया जा सकता। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने मौलाना के निधन को इस्लाम के लिए बहुत भारी क्षति बताया है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

रोजनामा सहारा (28 मई) के अनुसार जमीयत उलेमा हिंद की कार्यकारिणी ने महामंत्री मौलाना महमूद मदनी को मौलाना मंसूरपुरी की जगह जमीयत उलेमा का नया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है जिसका गठन 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किया गया था।

विश्व

जर्मनी में जिहादी संगठन पर प्रतिबंध

इंकलाब (6 मई) के अनुसार जर्मनी की सरकार ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन अंसार इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी घोषणा के अनुसार इस इस्लामिक संगठन के सोमालिया में सक्रिय मुस्लिम आतंकवादी संगठन अल शबाब और फिलिस्तीन के हमास जैसे संगठन से तार जुड़े हुए हैं और यह इनको नियमित रूप से आर्थिक सहायता देता आ रहा है। यह संगठन अपने नेटवर्क द्वारा विश्वभर में इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहन भी दे रहा है। जर्मनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर आतंकवाद का सफाया करना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि आतंकवाद को आर्थिक साधन उपलब्ध कराने वाले सभी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस्लामिक जिहादी संगठन पर प्रतिबंध की घोषणा होते ही जर्मनी के गुप्तचर विभाग ने जर्मनी के 16 में से दस क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर छापेमारी की जिनमें सौ से अधिक इस्लामिक जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यह जिहादी संगठन हालांकि आतंकवाद को बढ़ावा देता था मगर इसने सामाजिक सेवाओं का नकाब ओढ़ रखा था। इसकी वेबसाइट पर यह दावा किया जाता था कि यह संगठन देश और विदेश में लाचार और गरीब लोगों की आर्थिक सहायता करता है। इस सामाजिक सहायता की आड़ में इसके द्वारा विदेशों में सक्रिय इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। यह संगठन 2019 से ही सरकार की निगरानी में था और इसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती

थी। सरकारी सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह संगठन किशोरों को विदेशी इस्लामिक मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के नाम पर भेजा करता था जहां उन्हें आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन इस्लामिक मदरसों का संचालन सलफी विचारधारा वाले कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानों द्वारा किया जाता था जो कि सशस्त्र जहाज द्वारा इस्लामिक शासन स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। जर्मनी की गुप्तचर विभाग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि जर्मनी में सल्फी और वहाबी अतिवादी मुसलमानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इस समय इनकी संख्या 15 हजार के लगभग बताई जाती है। जबकि 2011 में इनकी संख्या सिर्फ 3 हजार ही थी। गुप्तचर संगठन इन अतिवादी मुस्लिमों के संगठनों और मस्जिदों एवं मदरसों की भी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। ताकि इस्लामिक आतंकवाद के प्रसार को रोका जा सके।

अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के लिए अमेरिकी विमान

इंकलाब (8 मई) के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो देशों की सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सैनिक वायुयान भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अमेरिकी सैनिकों पर बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए किया गया है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका ने 6-बी लड़ाकू विमान और एफ-18 लड़ाकू विमानों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। अगर जरूरत समझी गई तो अन्य अमेरिकी सैनिक विमानों को अफगानिस्तान भेजा जा सकता है ताकि वहां से अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी सूत्रों के अनुसार तालिबान सरकारी सैनिकों पर हर दिन 80 से 100 हमले कर रहे हैं। इसलिए उनकी रक्षा करना और सहायता देना बेहद जरूरी है। ताकि अफगान सेना अपने देश की सुरक्षा को बरकरार रख सके। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान जीत जाते हैं और वे काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना अफगान सैनिकों को किसी अन्य देश में प्रशिक्षित करे।

इसके अतिरिक्त अफगान वायु सेना को भी अमेरिका और सहायता देने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला रहे हैं मगर उसके बाद यह भी जरूरी है कि अफगान सैनिकों को इस काबिल बनाया जाए कि वे तालिबान का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकें। इस समय अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या तीन हजार और नाटो देशों के सैनिकों की संख्या साढ़े सात हजार बताई जाती है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि सितंबर महीने के बाद जब हम वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाते हैं तो अफगानिस्तान के सरकारी सैनिकों

के लिए ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है जिससे वे अपने देश की रक्षा कर सकें और आतंकवादी इस्लामिक संगठन अपने पैर न पसार सकें। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान के साथ-साथ इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी सक्रिय हैं।

बीबीसी ने 22 मई के प्रसारण में कहा है कि पाकिस्तान सरकार बलुचिस्तान में एक बहुत बड़ा सैनिक अड्डा स्थापित कर रही है जो कि वायु सेना का होगा। इस लक्ष्य से पाकिस्तान सरकार के रक्षा विभाग ने कई हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। जानकार सूत्रों ने दावा किया है कि यह सैनिक अड्डा पाकिस्तान सरकार अमेरिका के सहयोग से स्थापित कर रही है। इस सैनिक अड्डे पर अमेरिकी सेना को रखा जाएगा ताकि वह अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के जिहादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को नियंत्रित कर सकें। पाकिस्तान के रक्षा विभाग ने इस बात का खंडन किया है कि पाकिस्तान का कोई हवाई अड्डा अमेरिका को सौंपा जा रहा है। मगर प्रवक्ता ने इस बात का संकेत दिया है कि सैनिक जरूरतों को देखते हुए और पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए बलुचिस्तान में एक सैनिक अड्डा बनाए जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तो प्रवक्ता ने कहा कि भूमि का अधिग्रहण करना राज्य सरकार का काम है। इस हवाई अड्डे को बनने में अभी काफी समय लगेगा क्योंकि यह एक काफी विशाल परियोजना है। इस योजना को कार्यान्वित करना पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

काबुल में हुए धमाके में 50 छात्राओं की मौत

रोजनामा सहारा (10 मई) के अनुसार काबुल में एक महिला स्कूल में हुए दो बम धमाकों में कम-से-कम 50 छात्राएं मारी गई हैं और 100 के करीब घायल हुई हैं। यह धमाका शिया बहुल क्षेत्र दस्त-ए-बार्ची में स्थित सैयद अल-शुहादा स्कूल के समीप हुआ है। मरने वालों में अधिकांश शिया हैं। हालांकि इस धमाके की जिम्मेवारी किसी भी संगठन ने अभी तक नहीं ली है मगर आतंकवादियों के दोनों संगठन तालिबान और इस्लामिक स्टेट कट्टर सुन्नी हैं जो गत कई वर्षों से शियाओं के खून की होली खेलते आ रहे हैं। इस धमाके के बाद क्षेत्र के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किए। घायलों और मरने वालों को इस क्षेत्र से निकालने के लिए जो एंबुलेंस और बचाव विभाग के कार्यकर्ता गए थे उन पर स्थानीय लोगों ने हमला किया और उन्हें घायल कर दिया।

इंकलाब ने 10 मई के अपने एक विशेष संपादकीय में इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि 'लड़कियों की पढ़ाई के दुश्मन अफगानी दहशतगर्द'। समाचारपत्र ने कहा है कि काबुल के गर्ल्स स्कूल में हुए आतंकवादी हमले में कम-से-कम 60 लड़कियां मारी गई हैं और 100 से अधिक घायल हुई हैं। मरने वालों में

अधिकांश छात्राएं हैं। खबरों के अनुसार पहले स्कूल के बाहर एक कार में ब्लास्ट किया गया और फिर रॉकेटों से हमले करके पूरे स्कूल की जमीन को बच्चियों के खून से लाल कर दिया। इन लड़कियों का अपराध यह था कि वह पढ़ना चाहती थीं। जबकि आतंकवादी यह चाहते हैं कि मुसलमान बच्चियां जाहिल रहें। उनको बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाए। लड़कियां बस मर्दों की खिदमत करें। हमलोग तालिबान के दौर को भी देख चुके हैं कि किस तरह से महिलाओं के अधिकारों को कुचला गया। अब एक बार फिर महिलाओं की जान मुसीबत में है।

इस्लामिक आतंकवादी अनेक महिला डॉक्टरों की हत्या कर चुके हैं। न्यूज चैनलों की महिला एंकरों को भी बख्शा नहीं गया। महिला पत्रकारों के खून से भी होली खेली गई। अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान बहुत जल्दी महिलाओं की एक बड़ी कत्लगाह बन जाएगा। जो भी लड़की पढ़-लिखकर अपना कैरियर बनाना चाहेगी उसे कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल वहां पर इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां बहुत बढ़ चुकी हैं। यह नई फर्जी खिलाफत महिलाओं और औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसे हम सीरिया और इराक में देख चुके हैं। जिहाद अल-निकाह के नाम पर इराक और सीरिया में वहां की ईसाई और यजीदी महिलाओं की मंडियां सजाई गईं। उनसे सामूहिक बलात्कार किया गया।

आप यह भी जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट में ऐसे लोग शामिल थे जो पश्चिमी देशों के रहने वाले थे। सीरिया और इराक में हारने के बाद इनलोगों को वापस अपने देश में लौट जाना था। मगर पश्चिमी देशों ने अपने उन नागरिकों को वापस लेने से इंकार कर दिया जो जिहाद के नाम पर मध्य पूर्व पहुंचे थे। इसलिए इन लोगों में से कई लोगों को अफगानिस्तान में जाकर अपनी गतिविधियां शुरू करनी पड़ीं। जबसे इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई तो उसकी गतिविधियों से सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को हुआ। अब अफगानिस्तान के मामले में भी निर्दोषो की हत्या करके वह अमेरिका की मदद कर रही है। क्योंकि अमेरिका दुनिया को यह बताना चाहता है कि अगर उसने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई तो वहां पर अराजकता फैल जाएगी।

हकीकत यह है कि पिछले 20 वर्षों में अमेरिका ने एक बार भी इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि वह दुनिया को यह बताना चाहता है कि अफगानिस्तान की जनता तभी सुरक्षित रह सकती है जब अमेरिकी सेना वहां रहे। अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता करके दुनिया को यह भी बता दिया है कि वह लोकतंत्र पर नहीं बल्कि बंदूक में विश्वास रखता है। अब यह यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस जाते ही वहां की वर्तमान सरकार को तालिबान उखाड़कर फेकेंगे और वहां पर खून की होली का पुराना दौर शुरू हो जाएगा।

इस सच्चाई को सब जानते हैं कि तालिबान को कमजोर करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने इस्लामिक स्टेट नामक जिस संगठन को खड़ा किया था वह तालिबान के साथ जंग शुरू करेगा। मगर क्या किया जाए? मुस्लिम देश

पश्चिमी देशों की साजिशों में इस तरह से घिर गए हैं कि उनके निवासी हमेशा खून में नहाए रहेंगे। उनके शहर खंडहर बनते रहेगें और इस आतंकवाद का लेवल इस्लाम के माथे पर चिपकाया जाता रहेगा।

चीन अफ्रीका में फैला रहा है अपने पांव

इत्तेमाद (25 मई) के अनुसार चीन अफ्रीका में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इससे अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। चीन अफ्रीका के विभिन्न देशों में अपने सैनिक अड्डे भारी संख्या में स्थापित कर रहा है। हाल ही में इस संदर्भ में अमेरिकी सेना की अफ्रीकी कमांड के प्रमुख जनरल स्टीफन जे. टाउनसेंड ने कहा है कि चीन एक योजनाबद्ध तरीके से अफ्रीकी देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा है और वह इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। इनमें बिना ब्याज के ऋण देना और भारी मात्रा में चीनी कंपनियों का पूंजी निवेश के साथ-साथ उनके बच्चों को चीनी विश्वविद्यालय में मुफ्त शिक्षा देना भी शामिल है। हाल ही में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने मायाजाल में फंसाने के लिए चीनी सुंदरियों के इस्तेमाल करने के बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली हैं।

चीन ने 2017 में अफ्रीका के पूर्वी तट जिबूती में अपना पहला सैनिक अड्डा निर्माण किया था। इससे अमेरिकी रणनीतिकारों को बहुत परेशानी हुई है। क्योंकि उसके बगल में अमेरिका का सैनिक अड्डा कैंप लेमनियर है। उसी समय से चीन अफ्रीका के पड़ोसी देशों में भी अपने पैर पसार रहा है। हाल ही में उसने एक आधुनिक नौसैनिक अड्डा भी स्थापित किया है। इस अड्डे पर चीन के बड़े से बड़े जलयान भी लंगर डाल सकते हैं जिन पर उसके विमान और परमाणु अस्त्रों से लैश पनडुब्बियां भी अफ्रीकी तट में सफलतापूर्वक दाखिल हो सकते हैं।

अब चीन ने अपना अगला निशाना तंजानिया को बनाया है। वहां पर उसने कम-से-कम तीन जगह अपने सैनिक अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। उन अड्डों में चीनी सेनाएं जब चाहें ईंधन, खाने-पीने का सामान और आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इन अड्डों में हाल ही में चीन ने कुछ पनडुब्बियां भी पहुंचाई है, जिसके कारण पश्चिमी देश काफी परेशान हैं। क्योंकि अभी तक अफ्रीकी समुद्रों पर पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व था। मगर अब उन्हें चीन ने चुनौती देनी शुरू कर दी है।

चीन ने अफ्रीका के विभिन्न देशों में साठ अरब डॉलर का पूंजी निवेश किया है। इस समय चीन छोटे-छोटे अफ्रीकी देशों के साथ ही राजनयिक संबंध स्थापित करने में विशेष रुचि ले रहा है। इस समय 52 अफ्रीकी देशों में चीनी दूतावास मौजूद हैं। जबकि अमेरिकी दूतावासों की संख्या 49 ही है। हाल ही में चीन ने विभिन्न अफ्रीकी देशों को अस्त्र-शस्त्र बेचने का भी धंधा शुरू किया है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की तुलना में उसके अस्त्र-शस्त्र काफी सस्ते हैं।

इसके अतिरिक्त इन देशों के सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी चीन ने विशेष अभियान शुरू कर रखा है। अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो उसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं।

अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति की विद्रोहियों द्वारा हत्या

अवधनामा (22 फरवरी) के अनुसार अफ्रीकी देश चाड के 68 वर्षीय राष्ट्रपति इदरिस डेबी की विद्रोहियों ने युद्ध में हत्या कर दी है। वे गत 30 वर्षों से इस अफ्रीकी देश में सत्तारूढ़ थे। संवाद समिति के अनुसार स्वर्गीय राष्ट्रपति के बेटे को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति इदरिस डेबी ने 1990 में सत्ता संभाली थी और वे अफ्रीका में कई दशक तक सत्ता की बागडोर संभालने वाले कुछ राष्ट्रपतियों में शामिल थे। उनका तख्ता पलटने के लिए विद्रोहियों द्वारा अनेक बार प्रयास किया गया था मगर ये प्रयास विफल रहे। अब हाल ही में विद्रोहियों ने चाड के उत्तरी भागों में सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चाड में लगभग गृहयुद्ध की स्थिति है। अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी को सेना का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। मगर अब सेना में भी विभाजन हो गया है।

बताया जाता है कि जिस राष्ट्रपति की विद्रोहियों ने हत्या की है उनके फ्रांस और अमेरिका के साथ घनिष्ठतम संबंध थे। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि चाड में विद्रोह की ज्वाला भड़काने के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ है। इदरिस डेबी ने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। विपक्षी दलों ने इस चुनाव में भाग लेने से इंकार कर दिया था और यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति इस चुनाव में धांधली कर रहे हैं। समाचारपत्रों का कहना है कि चाड में हाल ही में इस्लामिक आतंकवादियों के हमले में जो वृद्धि हुई है उसके पीछे लीबिया का हाथ है। इदरिस युद्ध में जख्मी हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए राजधानी लाया गया था। इसके साथ ही पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और राष्ट्रीय असेंबली को भंग करके देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सैनिक प्रवक्ता ने कहा है कि सेना विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और हम किसी भी बाहरी ताकत को अपने देश पर कब्जा नहीं करने देंगे। आपातकाल की घोषणा होते ही चाड से नागरिकों के पलायन का सिलसिला तेज हो गया। लोग भागकर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं।

पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक

शांति का महीना रमजान यरुशलम में इजरायल और हमास के बीच खूनी झड़पों में गुजर गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इन झड़पों में 227 फिलिस्तीनी मारे गए और 1620 लोग घायल हो गए। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन हमलों में इजरायल के सात सैनिक और 11 नागरिक मारे गए और 50 के करीब घायल हो गए। इस युद्ध में इजरायल ने अपनी वायुसेना, टैंकों, प्रक्षेपास्त्रों का खुलकर इस्तेमाल किया। जबकि हमास ने दस हजार रॉकेट और मिसाइल चलाए। इजरायली सेना ने अनेक भवनों को ध्वस्त कर दिया जिसके कारण उनमें रहने वाले एक लाख लोग बेघर हो गए। हमास का कहना है कि इजरायल ने जानबूझकर आवासीय क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया था। जबकि इजरायल का दावा है कि हमास ने रिहाइसी भवनों में अपने अड्डे बना रखे थे, जिनमें रॉकेट और मिसाइल बनाए जाते थे। इसलिए चुन-चुनकर सिर्फ उन्हीं भवनों को इजरायली सेना ने अपना निशाना बनाया। उन पर हमला करने से पूर्व उनमें रहने वाले लोगों को बकायदा नोटिस दिए गए थे कि वे इन हमलों से पूर्व इन भवनों को खाली कर दें ताकि इनमें कोई निर्दोष व्यक्ति न मारा जाए।

खास बात यह है कि तुर्की और ईरान को छोड़कर अरब जगत के बाकी सभी देश मूकदर्शक बने रहे। सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर में मुसलमानों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन किए। भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद एक

दर्जन से अधिक नगरों में मुसलमानों ने इजरायल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए और भारत सरकार से मांग की कि वह खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन करे। इस संघर्ष का विश्व युद्ध में बदलने का खतरा पैदा हो गया। क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ने इस युद्ध में शामिल होने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ, मिस्र, अमेरिका आदि के दबाव के कारण हालांकि इजरायल और इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के बीच युद्धविराम हो गया है। मगर दोनों पक्षों के बीच काफी तनाव बढ़ रहा है। युद्धविराम के बाद फिलिस्तीनी जब मस्जिद अल-अक्सा में जश्न मना रहे थे तो इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चलाई जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए। हमास ने यह धमकी दी है कि हम इजरायल को खत्म करके ही दम लेंगे। दूसरी ओर इजरायल ने भी कड़े तेवर अपनाते हुए कहा है कि हम इस युद्ध को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे।

इस्लाम में क्योंकि स्वदेश की कोई कल्पना नहीं है और वह दुनिया भर के मुसलमानों को मिल्लत मानता है। इसी कारण इस युद्ध के खिलाफ विश्व भर में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। जहां तक भारत का संबंध है अन्य भाषाओं के समाचारपत्रों ने कोरोना महामारी के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जबकि उर्दू अखबारों में इस दौरान यरुशलम युद्ध से संबंधित समाचार छाए रहे।

इत्तेमाद (17 मई) ने इस संदर्भ में मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'तुम फिलिस्तीनियों को खामोश नहीं कर सकते'। इसी समाचारपत्र के 16 मई के अंक में प्रकाशित मुख्य समाचार का शीर्षक है, 'इजरायली बमबारी में रिफ्यूजी कैंप, मीडिया बिल्डिंग भी निशाना बने', 'एक ही परिवार के आठ बच्चे और दो महिलाएं मारी गईं' 'गाजा में 140 फिलिस्तीनी शहीद, जिनमें 39 बच्चे शामिल', 'दस हजार फिलिस्तीनी स्कूल भवनों में शरण लेने पर विवश', 'संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद और ओआईसी के अधिवेशन में विस्फोटक स्थिति पर विचार'।

सियासत (20 मई) का शीर्षक है, 'इजरायली हमले जारी', 'गाजा में और मौतें', 'विश्व बिरादरी मूकदर्शक'। इसी समाचारपत्र के 18 मई में प्रकाशित समाचार का शीर्षक है, 'इजरायली बमबारी जारी', '218 फिलिस्तीनी मारे गए'। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने अपनी बैठक में यह सुझाव दिया है कि इजरायल के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम देशों को मिलकर कोई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कवच फिलिस्तीनियों के लिए बनाना चाहिए। इसके लिए सभी मुस्लिम देशों को मिलकर सुरक्षा सेना भर्ती करनी चाहिए। बैठक में मांग की गई कि फिलिस्तीन की समस्या का समाधान 2018 में पारित प्रस्ताव के अधीन होना चाहिए।

सियासत (19 मई) के अनुसार फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इजरायली हमलों में मरने वालों में एक तिहाई मासूम बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हालांकि इजरायल के भी काफी लोग मरे हैं मगर उनके आंकड़ों को इजरायल जानबूझकर छिपा रहा है।

इसी समाचारपत्र ने 20 मई के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें 'इंडियन फ्रेंड्स फॉर फिलिस्तीन' ने कोलकाता में आयोजित एक बैठक में इजरायल के अतिक्रमण के खिलाफ भारत द्वारा अपनाए गए रूख की प्रशंसा की है। संगठन के प्रवक्ता और पूर्व सांसद केसी त्यागी ने कहा है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके जंग बंद करवानी चाहिए। इजरायल ने फिलिस्तीन की भूमि पर जो जबरन कब्जा कर रखा है उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।

सियासत (23 मई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि फिलिस्तीन की समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र को दो देशों में बांट दिया जाए और इसकी राजधानी संयुक्त रूप से यरुशलम हो। उन्होंने कहा कि मैं इजरायल का समर्थक हूं मगर इसके साथ ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश भी बनाया जाना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 मई) के अनुसार विश्व सूफी आंदोलन के अध्यक्ष मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन खान ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि एक ओर तो इजरायल निर्दोष फिलिस्तीनियों की खून से होली खेल रहा है और दूसरी ओर मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को किसी तरह की सहायता देने की बजाय मूकदर्शक बने हुए हैं। मुस्लिम देशों की यह खामोशी उनकी बुजदिली का सबूत है। क्योंकि मुस्लिम देशों के अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष अय्याश और स्वार्थी हो गए हैं तथा वे इस्लाम से दूर चले गए हैं। उन्होंने विश्वभर के मुसलमानों से अपील की कि वे इजरायल के बने हुए उत्पादनों का बहिष्कार करें।

इसी समाचारपत्र ने 29 मई के अंक में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 24 और विरोध में 9 वोट पड़े। भारत सहित 11 अन्य देश तटस्थ रहे। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध बंद करने की अपील करते हुए इजरायल को हमलावर करार दिया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से इजरायली सेना फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है वह अपराध है और उसकी जांच होनी चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने 22 मई के अंक में युद्धविराम का विश्लेषण करते हुए एक संपादकीय में कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री की मर्जी के खिलाफ युद्धविराम हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार-बार लम्बे युद्ध की धमकी दे रहे थे। क्योंकि वे चाहते थे कि युद्ध चलता रहे और उनके विरोधी नई सरकार का गठन न कर सकें।

समाचारपत्र ने कहा है कि एक ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजरायल का समर्थन करते रहे मगर गुप्त रूप से उन्होंने मिस्र और कतर पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे हमास को युद्धविराम के लिए तैयार करें और फिर इजरायल को भी इस युद्धविराम को कबूल करने के लिए तैयार कर लिया। समाचारपत्र ने दावा किया है कि हमास की जबर्दस्त बमबारी के कारण इजरायल को युद्धविराम के प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा है। समाचारपत्र ने युद्धविराम को फिलिस्तीनी कौम की विजय और इजरायल की हार की संज्ञा दी है।

हमारा समाज ने 23 मई को मुख्य समाचार के रूप में 230 फिलिस्तीनियों के मारे

जाने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

इत्तेमाद (14 मई) के अनुसार गाजा में ईद के मौके पर इजरायली सेना ने जबर्दस्त बमबारी की जिसमें 87 फिलिस्तीनी मारे गए। इसी समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि गाजा पर इजरायल के 150 युद्ध विमानों ने हमला किया जिसके कारण सैकड़ों इमारतें मलवे में बदल गईं। इजरायल के हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। जॉर्डन और लेबनान की जनता हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी जनता की हिमायत में गाजा की सीमा की ओर बढ़ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह घोषणा की है कि मासूम फिलिस्तीनियों के खून का बदला इजरायल से हर कीमत पर लिया जाएगा।

अवधनामा (17 मई) ने एक समाचार में यह दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर में अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में उग्र प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसे सैनिकों ने विफल बना दिया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक विजय कुमार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उर्दू समाचारपत्रों ने हमास और इजरायल के युद्ध पर दर्जनों संपादकीय प्रकाशित किए हैं, जिनमें इजरायल की निंदा की गई है।

अवधनामा (7 मई) ने मस्जिद अल-अक्सा के संबंध में खुर्शीद आलम दाऊदी कासमी का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद अल अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। पैगम्बर-ए-इस्लाम और उनके सहयोगी सैकड़ों वर्ष तक मस्जिद अल-अक्सा की ओर रूख करके नमाज अदा करते रहे हैं। इस्लामी इतिहास के अनुसार शब-ए-मेराज के मौके पर फरिश्ते हजरत मोहम्मद को मक्का से मस्जिद अल-अक्सा में नमाज अदा करने के लिए ही लाए थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मई) में शकील रशीद का एक विशेष लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें दुनिया के मुसलमानों से यह अपील की गई है कि वे मस्जिद अल-अक्सा के फरियाद को सुनें और फिलिस्तीन की लाचार जनता को इजरायल के चंगुल से आजाद करवाएं।

इंकलाब (15 मई) ने भी एक संपादकीय में इजरायल की निंदा करते हुए भारत सरकार से मांग की है कि वह फिलिस्तीन का समर्थन करे और इजरायल पर इस बात के लिए दबाव डाले और वह फिलिस्तीन के उन क्षेत्रों को खाली करे जिस पर उसने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है।

रोजनामा सहारा (22 मई) ने भी अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल का समर्थन करने की बजाय मतदान में भाग न लेकर फिलिस्तीन का समर्थन किया। समाचारपत्र का कहना है कि भारत शुरू से ही फिलिस्तीन का समर्थक रहा है और मोदी सरकार को भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए।

सियासत (23 मई) ने अपने संपादकीय में इजरायल हमास युद्धविराम फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि इस युद्धविराम को स्थाई रूप दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में

युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके। क्योंकि इजरायल के इरादे नेक नहीं हैं और वह पूरे फिलिस्तीन को हड़पना चाहता है। इसलिए वह किसी न किसी बहाने से बारबार युद्ध छेड़ देता है। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि हाल के युद्ध में इजरायल को जो मुंह की खानी पड़ी है उसका वह हर कीमत पर बदला लेगा। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह इजरायल पर भविष्य में युद्ध न छेड़ने के लिए दबाव डाले।

इत्तेमाद (18 मई) ने अपने संपादकीय में इजरायल और हमास के युद्ध पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इजरायल जिस तरह से जबरन फिलिस्तीनियों को उनके पैतृक स्थानों से बेदखल करके वहां कब्जा जमा रहा है वह घोर निंदनीय है। उसका डटकर विरोध करने के लिए दुनिया भर के मुसमलानों को एकजुट हो जाना चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने 21 मई के संपादकीय में फिलिस्तीन के मामले में अमेरिका द्वारा दोहरा रूख अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि एक ओर तो अमेरिका इजरायल से युद्धविराम की मांग करता है और दूसरी ओर परोक्ष रूप से वह इजरायल को युद्ध सामग्री के साथ-साथ आर्थिक सहायता प्रदान करता है। हाल ही में शेख जराह में सदियों से रह रहे फिलिस्तीनियों को वहां से बेदखल करके वहां पर यहूदियों को बसाया गया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का खुला उल्लंघन है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका इस संबंध में मूकदर्शक बना हुआ है।

हमारा समाज (17 मई) ने आबिद अनवर का एक संपादकीय प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि फिलिस्तीनी जनता इजरायली अतिक्रमण के खिलाफ बेबस है। जबकि मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीनियों की सहायता करने की बजाय चुप्पी साध रखी है। यह हजरत मोहम्मद और उनकी शिक्षाओं के सरासर खिलाफ है।

हमारा समाज ने 16 मई के संपादकीय में इस्लामिक देशों के सहयोग संगठन से आशा व्यक्त की है कि वह विश्व के विभिन्न मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनी जनता की सहायता और इजरायल का विरोध करने के लिए प्रेरित करे।

पृष्ठभूमि : गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजरायल के भूमध्यसागर तट पर स्थित है। इस क्षेत्र में हमास का शासन है। इस इलाके को हड़पने के लिए इजरायल कई बार कोशिश कर चुका है। मगर हमास के कारण उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। यह संगठन फिलिस्तीन लिब्रेशन संगठन ने स्थापित किया था और इसने इजरायल को मान्यता देने से इंकार कर दिया था। 2017 में इस संगठन की ओर से यह घोषणा की गई कि उसका युद्ध यहूदियों से नहीं बल्कि फिलिस्तीन पर काबिज लोगों से है। अगर इजरायल उन क्षेत्रों को खाली कर दे जिस पर उसने 1967 के युद्ध में जबरन कब्जा किया था तो वे इजरायल के साथ स्थाई शांति के लिए तैयार है। कहा जाता है कि हमास को ईरान आदि कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है। उसकी विचारधारा इख्वानुल मुस्लिमीन की तरह है, जिसे सुन्नी आतंकवादी संगठन माना जाता है, जिस पर लगभग सभी अरब देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। शेख अहमद यासीन जो कि इख्वानुल मुस्लिमीन का नेता था

उन्होंने 1988 में हमास की नींव रखी थी। तबसे निरंतर हमास इजरायलियों का सशस्त्र विरोध करता आ रहा है। उसने अपने घोषणापत्र में कहा है कि फिलिस्तीन इस्लामिक वक्फ संपत्ति है जो कयामत तक मुसलमानों की ही रहेगी और फिलिस्तीन की समस्या का एक ही हल है और वह यह है कि सशस्त्र जिहाद द्वारा दुश्मनों का नामोंनिशान मिटा दिया जाए। ओसलो संधि के समय हालांकि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) ने इजरायल के वजूद को मान लिया था और उसने फिलिस्तीन को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करने का सुझाव दिया था मगर हमास ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

इतिहासकारों के अनुसार इजरायल-फिलिस्तीन की समस्या हजारों वर्ष पुरानी है और इसका उल्लेख बाइबिल में भी मिलता है। बाइबिल में कहा गया है कि यह क्षेत्र खुदा ने यहूदियों को बख्शा था मगर बाद में रोमन सेना ने उन्हें वहां से निकाल दिया। रोमनों के बाद इस क्षेत्र पर ईसाईयों का शासन रहा। ईसाईयों से इसे मुसलमानों ने छीन लिया और यहूदियों को वहां से भागकर विश्व के अनेक देशों में शरण लेनी पड़ी।

पहले विश्व युद्ध में उस्मानी साम्राज्य जर्मनी का सहयोगी था और इस युद्ध में उसे ब्रिटेन के हाथों हार हुई थी। ब्रिटेन ने उस्मानी साम्राज्य को छोटे-छोटे विभिन्न राज्यों में बांट दिया और उनका शासन अपने समर्थकों को सौंप दिया। तब ब्रिटेन ने यह घोषणा की थी कि पूरे यूरोप में फैले हुए यहूदियों के लिए फिलिस्तीन उनका पैतृक घर है। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने का जब प्रयास किया तो उसका विरोध अरबों ने किया। ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में यहूदियों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया। हिटलर के उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए यहूदी भारी संख्या में इस क्षेत्र में आबाद होने शुरू हुए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में विभाजित करने के लिए मतदान किया। इसके तहत यरुशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को यहूदियों ने तो मान लिया मगर अरबों ने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना था कि सारा फिलिस्तीन अरबों का है और वे उसमें से एक इंच भूमि भी यहूदियों को देने के लिए तैयार नहीं हैं।

मार्च 1948 में पहली बार अरबों और यहूदियों में संघर्ष हुआ। ब्रिटेन ने यहूदियों को यह आश्वासन दिया था कि वे उनके लिए एक आजाद संप्रभु राष्ट्र इजरायल की स्थापना करेंगे। मगर अरबों के रूख को देखते हुए ब्रिटेन को इजरायल की स्थापना की घोषणा करने की हिम्मत नहीं हुई और वे फिलिस्तीन को छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद यहूदी नेताओं ने इजरायल नामक देश की घोषणा कर दी। इसका विरोध फिलिस्तीनी मुसलमानों ने किया। युद्ध के दौरान कई फिलिस्तीनियों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध की समाप्ति के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में जॉर्डन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था उसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। जबकि मिस्र ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था उसे गाजा की पट्टी कहा जाता है।

1967 में हुए एक अन्य युद्ध में इजरायल ने पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा

कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने सीरिया से गोलन हाइट्स और मिस्र के सिनाई क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। इजरायल पूरे यरुशलम पर अपना दावा करता है जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरुशलम को अपना मानते हैं। इजरायल के दावे को मान्यता देने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन सहित अनेक देश शामिल हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि इजरायल उनका उत्पीड़न करता है। हाल का विवाद रमजान के पवित्र महीने में तब शुरू हुआ जब इजरायली सैनिकों ने मस्जिद अल-अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए गए मुसलमानों को रोका और उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई मुसलमान घायल हो गए। सेना पर हमला करने के आरोप में इजरायल ने कई मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया। विवाद का दूसरा कारण शेख खैर की अरब बस्ती बनी। इजरायल सरकार का दावा है कि यह भूमि उनकी है और उस पर मुसलमानों ने जबरन कब्जा कर रखा है। गत महीने इजरायली सेना ने वहां पर बसे हुए 2000 परिवारों को बेदखल कर दिया। इस बेदखली का विरोध फिलिस्तीनी सरकार और हमास ने किया। इसके बाद दोनों पक्षों में सशस्त्र संघर्ष भड़क उठा।

मिस्र फ्रांस से राफेल विमान खरीदेगा

इंकलाब (5 मई) के अनुसार मिस्र ने फ्रांस से साढ़े चार अरब डॉलर में तीस राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। समझौते की पुष्टि मिस्र के रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। फ्रांस 2013 से लेकर 2017 तक मिस्र को अस्त्र-शस्त्र बेचने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। संवाद समिति के अनुसार इसके अतिरिक्त मिस्र ने मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरण भी खरीदे हैं, जिस पर 20 करोड़ यूरो खर्च होंगे। फ्रांस के इस सौदे पर फ्रांसीसी समाचारपत्रों ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि मिस्र में लोकतंत्र नहीं बल्कि सैनिक तानाशाही है। मिस्र में सैनिक जनरल अब्दुल फतह अल-सीसी ने 2013 में इख्वानुल मुस्लिमीन के निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाकर उस पर कब्जा कर लिया था। तब से वहां पर सैनिक तानाशाही चली आ रही है। इख्वानुल मुस्लिमीन

पर प्रतिबंध है और उससे जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया है। जबकि 1000 से अधिक लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है।

इससे पूर्व भी फ्रांस ने 2017 में मिस्र को 24 युद्ध विमान बेचने के बारे में एक समझौता किया था। मगर मीडिया और जनता के विरोध के कारण सरकार को इस सौदे को रद्द करना पड़ा था।

सऊदी अरब में क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर देश से निष्कासन

रोजनामा सहारा (5 मई) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दो वर्ष की कैद और दो लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई विदेशी नागरिक इसका उल्लंघन करता है तो इसे सदा के लिए देश से निष्कासित कर दिया जाएगा और भविष्य में उसके सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें दो सप्ताह तक अपने घरों में क्वारंटीन रहना होगा। सरकार उनकी सख्त निगरानी करेगी। देश से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज ले रखी है। जो विमान सेवा इस निर्देश का उल्लंघन करेगी उसके जहाजों को भविष्य में सऊदी अरब में दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी। कुवैत सरकार ने भी इस बात की घोषणा की है। ■

ईरान मोरक्को के लिए खतरा

रोजनामा सहारा (8 मई) के अनुसार मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बौरीता ने कहा है कि ईरान मोरक्को के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे रबात में अमेरिकी इजरायल पब्लिक अफेयर कमेटी द्वारा आयोजित एक समारोह में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और विद्रोहियों को हर तरह की सहायता दे रहा है ताकि वह मोरक्को की वर्तमान सरकार

का तख्ता पलट सके। उन्होंने कहा कि ईरान ने पोलिसारियो फ्रंट के कैडर को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए हैं। इसके अतिरिक्त उसके कैडर को ईरानियों द्वारा युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान हिज्बुल्लाह नामक इस्लामिक जिहादी संगठन के माध्यम से अफ्रीकी देशों में इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है।

नासिर ने कहा कि हालांकि हम ईरानी खतरे का मुकाबला कर रहे हैं। मगर उसके लिए हमें अपने सहयोगियों की सहायता की भी जरूरत है। मोरक्को की इस घोषणा के बाद जर्मनी सरकार ने विचार विमर्श के लिए अपने राजदूत को मोरक्को से जर्मनी बुलाया है। मोरक्को ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी सहारा क्षेत्र में हालांकि अमेरिका ने मोरक्को क्षेत्र के कब्जे को मान्यता प्रदान की है मगर जर्मनी उसका विरोध कर रहा है। जर्मनी ने हाल ही में मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद मोरक्को द्वारा पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर कब्जे से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए बंद कमरे में अधिवेशन बुलाए।

कतर के वित्त मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त

रोजनामा सहारा (8 मई) के अनुसार कतर के वित मंत्री अली शरीफ अल-अमादी को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पद से हटा दिया गया है। कतर के अमीर के आदेश से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अमीर ने यह निर्देश दिया है कि शरीफ अल-अमादी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच की जाए। कतर की सरकार ने आरोप लगाया है कि पूर्व वित्त मंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी फंड में काफी घोटाला किया है और काफी मात्रा में धन गैरकानूनी तौर से विदेश भेजा है। जहां उसका पूंजी निवेश किया गया है। अली शरीफ अल-अमादी मूल रूप से एक बैंकर हैं। उन्होंने कतर के नेशनल बैंक के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। इससे प्रभावित होकर कतर के अमीर ने 2013 में उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया था। हालांकि सरकारी तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि उन्होंने कितनी धनराशि को गबन किया है। फिर भी जानकार सूत्रों के अनुसार गबन की गई धनराशि एक अरब डॉलर बताई जाती है।

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन

इंकलाब (4 मई) के अनुसार बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली में दफन कर दिया गया। कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है। इसलिए उन्होंने उनकी मौत की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन के परिवारजन उनके शव को बिहार में दफनाना चाहते थे मगर भारत सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। कब्रिस्तान में भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनके शव को दफना दिया। मगर बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान वहां पहुंच गए। मगर उन्हें कब्रिस्तान के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया। शहाबुद्दीन के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि जब शहाबुद्दीन हाई सिक्योरिटी सेल में बंद थे तो प्रशासन ने उनके सेल में जानबूझकर कोरोना से प्रभावित एक पाकिस्तानी को रखा ताकि वे संक्रमित हो सकें। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे।

सऊदी अरब से 1100 पाकिस्तानी कैदी वापस

रोजनामा सहारा (11 मई) के अनुसार पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के दौरे के नतीजे के तौर पर सऊदी सरकार ने वहां की जेलों में बंद 1100 पाकिस्तानी कैदियों को वापस स्वदेश भेजने की घोषणा की है। उन्होंने जेद्दा में उर्दू न्यूज से वार्ता करते हुए कहा कि जुर्माने अदा न करने के कारण कई सौ पाकिस्तानी सऊदी जेलों में बंद हैं। अगर हमें एक अरब रुपये कहीं से मिल जाएं तो हम उन्हें भी वापस ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी जेलों में 30 पाकिस्तानी कैदी ऐसे हैं जो कि हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें वहां की अदालत मौत की सजा दे चुकी हैं। हम उनको पाकिस्तान वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 1100 पाकिस्तानी कैदी वापस स्वदेश पहुंच जाएंगे।

अमेरिकी नौसेना द्वारा अस्त्र–शस्त्र जब्त

रोजनामा सहारा (10 मई) के अनुसार अमेरिकी नौ सेना ने समुद्र में छापे मारकर अस्त्र-शस्त्रों से लदे हुए एक जलयान को कब्जे में लिया है। बताया जाता है कि ये अस्त्र-शस्त्र ईरान द्वारा यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के लिए भेजा जा रहा था। ईरानी मीडिया के अनुसार हूतियों ने सऊदी अरब के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में हूतियों के जनरल ने सऊदी अरब के उस क्षेत्र का दौरा किया जो कि अब हूतियों के कब्जे में है। जो अस्त्र-शस्त्र जब्त किए गए हैं उनमें मिसाइल, रॉकेट, मोर्टार और कई तरह की राइफलें आदि शामिल हैं। हूती 2014 से यमन की राजधानी साना और उसके आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होंने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है।

यरुशलम में बाबा फरीद की सराय

इंकलाब (21 मई) के अनुसार यरुशलम में 800 वर्ष पुरानी एक दरगाह और सराय है जो कि एक भारतीय दरवेश फरीदुद्दीन गंजशकर ने स्थापित की थी। कहा जाता है कि बाबा फरीद हज करने के लिए आए थे और उन्होंने काफी समय यरुशलम में व्यतीत किया जहां उनकी दरगाह और सराय मौजूद है। इस सराय के वर्तमान रखवाले का नाम मोहम्मद मुनीर अंसारी है जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और गत साठ वर्ष से इस सराय और दरगाह की देखभाल कर रहे हैं। इस सराय में कोई भी भारतीय मुफ्त ठहर सकता है और उसके खाने-पीने की भी मुफ्त व्यवस्था शताब्दियों से चली आ रही है।

इमरान खान का सऊदी दौरा

सियासत (10 मई) के अनुसार पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास तेज कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था। उन्होंने उमरा करने के अतिरिक्त पैगम्बर के मजार पर भी हाजिरी दी थी और मदीना में मस्जिद-ए-नबवी में जाकर नमाज पढ़ी। समाचारपत्रों के अनुसार इमरान सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी दौरे पर आए थे। इससे पूर्व पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अचानक सऊदी अरब का दौरा किया था। उन्होंने वहां के युवराज के साथ-साथ सऊदी सेना प्रमुख और अन्य उच्च सैनिक अधिकारियों से भी बंद कमरे में लंबी मुलाकातें की थी। सऊदी समाचारपत्रों के अनुसार जब कमर जावेद बाजवा से उनके सऊदी अरब दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारा पुराना दोस्त है। दोनों देशों के सामने जो रक्षा संबंधी समस्याएं हैं उनको मिलकर हल करने के बारे में इन बैठकों में विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इससे अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

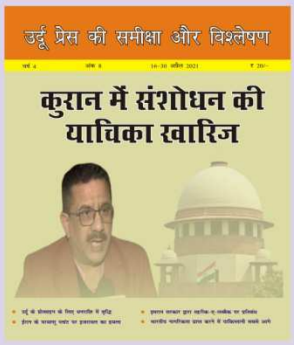

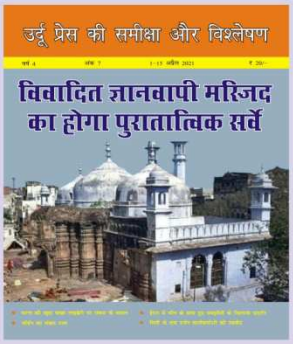

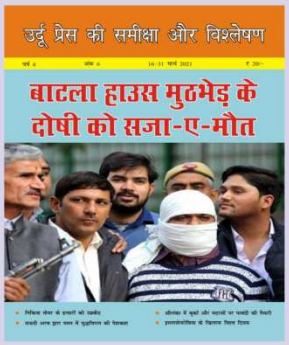

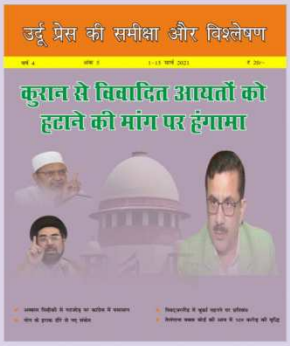

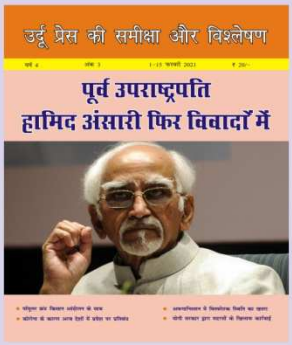

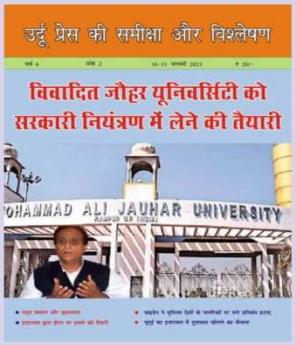

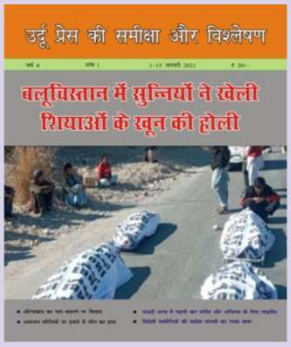

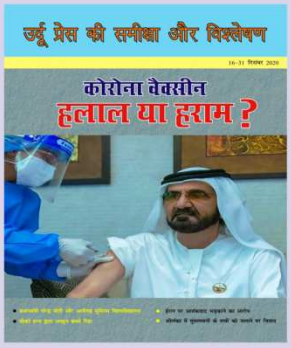

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रतीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, वेबसाइट : indiapolicy@gmail.com